प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
27.06.2017 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

जीएसटी
केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्रोत पर कर–कटौती टी डी एस और स्रोत पर कर–संग्रह–टी सी एस के प्रावधानों का अमल फिलहाल स्थगित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह निर्णय उद्योग और व्यापार जगत से मिली प्रतिक्रियाओं के मददेनजर लिया गया है। बयान में कहा गया है कि जो लोग स्रोत पर कर कटौती या संग्रह के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराना होगा, लेकिन कर की कटौती या संग्रह की जिम्मेदारी उस दिन से मानी जाएगी, जब इन धाराओं पर अमल शुरू होगा।

अधिसूचना
उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य बनाने की केन्द्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की अवकाश पीठ ने कहा कि सिर्फ इस आशंका पर अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता कि सरकार आधार न होने के कारण लोगों को विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रख सकती है।
अपर सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केन्द्र सरकार ने उन लोगों के लिए आधार पंजीकरण सीमा तीस जून से बढ़ाकर तीस सितम्बर कर दी है जो अभी इसके बिना कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख सात जुलाई तय की है।

कौल सिंह
स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि द्रंग क्षेत्र में पेयजल योजनाओं पर इस वर्ष पांच करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। क्षेत्र की टांडू पंचायत के नेरी गांव में उठाऊ पेयजल योजना के लोकार्पण के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये जानकारी दी। कौल सिंह ने कहा कि द्रंग नमक खान का कार्य दोबारा शुरू करने के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और खान से नमक निकालने का कार्य आगे बढ़ा है। इसके बाद उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया।

निर्वाचन
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र ज़िला स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस सम्बन्ध में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र चौहान ने बिलासपुर के उपायुक्त व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने ई.वी.एम. की वर्तमान स्थिति व बाहरी राज्यों से लाई जाने वाली नई ई.वी.एम. मशीनों के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। तहसीलदार निर्वाचन वीना कुमारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ज़िले में समय रहते सभी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

धर्माणी
बिलासपुर ज़िले के घुमारवीं स्थित सिविल अस्पताल में मुख्य संसदीय सचिव राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में आज रोगी कल्याण समिति की एक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य व उप–स्वास्थ्य केन्द्रों में मधुमेह, एच.बी. और रक्तचाप की मुफ्त जांच के अलावा लोगों को 66 किस्म की दवाईयां भी निःशुल्क दी जा रही हैं। धर्माणी ने कहा कि शिशु जननी कार्यकम के तहत गर्भवती महिलाओं को दवाईयों व एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त दी जा रही है।

बीएसएनएल
भारत संचार निगम लिमिटेड बी.एस.एन.एल. के शिमला ज़िला महाप्रबंधक एम.सी. सिंह ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार निगम ने मोबाईल कनैक्शनों को आधार

नम्बर से लिंक करने का कार्य शुरू कर दिया है। शिमला में निगम के मुख्य महाप्रबंधक एस. के.गुप्ता ने आज मोबाईल आधार लिंक योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश के 22 लाख मोबाईल उपभोक्ताओं को अगले वर्ष 6 फरवरी से पहले आधार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि नया कनैक्शन अब आधार से लिंक होने के बाद ही एक्टीवेट होगा। एस. के.गुप्ता ने बताया कि इससे फर्जी तरीके से मोबाईल सिम लेने और उसका दुरूपयोग करने वालों पर लगाम लगेगी।

शिमला–भाजपा

स्वच्छ भारत अभियान के तहत भाजपा ने आज शिमला शहर के सभी 34 वार्डों में साफ–सफाई की। इस मौके पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपने आसपास के क्षेत्र को साफ–सुथरा रखने और स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इस अभियान में बूथ अध्यक्ष नरेश शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

फायरिंग

कांगड़ा ज़िले में धर्मशाला की सकोह फायरिंग रेंज में कल 28 जून को अस्थायी तौर पर फायरिंग की अनुमति दी गई है। सहायक आयुक्त शशि पाल नेगी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि समादेशक द्वितीय भारतीय रिज़र्व वाहिनी सकोह द्वारा सुबह 8 से शाम 5 बजे तक फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। उन्होंने सराह, अप्पर सकोह, वनवाला, जटेहड़ पंचायत सहित साथ लगते अन्य क्षेत्रों के लोगों से इस दौरान फायरिंग रेंज से दूर रहने की अपील की है।

गोरखा समुदाय

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स में चल रहे गोरखा समुदाय के आंदोलन का हिमाचल व पंजाब गोरखा एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है। धर्मशाला में आज समुदाय से संबंधित हज़ारों लोगों ने शांतिपूर्ण बैठक की और उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह राणा ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार दार्जिलिंग हिल्स में बंगाली भाषा को जबरदस्ती लोगों पर थोप रही है। उन्होंने कहा कि गोरखा समुदाय के लोगों ने देश की आजादी के लिए अनेकों कुर्बानियां दी हैं और ममता बैनर्जी द्वारा उन्हें आतंकवादी कहना बेहद निंदनीय है।